Social Justice Union Govt. Registered

दैनिक न्याय साक्षी

अधिकार से न्याय तक

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्यायसाक्षी अधिकार से न्याय तक का सर्वे का कार्य तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्वे की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO - CHHHIN/2018/76480 || Postal Registration No-055/Raigarh DN CG || रायगढ़, गुरूवार 20 फरवरी 2020 || पृष्ठ-4, मूल्य 3 रूपए || वर्ष-02, अंक- 143

अब किसान खुद तय करेंगे, फसल बीमा लेना है या नहीं

» मोदी सरकार का देश के किसानों का बड़ा तोहफा

नई दिल्ली (आरएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में मंत्रिमंडल ने किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को अब स्वैच्छिक बना दिया है। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट के किसानों के लिए फसल बीमा का 90 फीसदी प्रीमियम सरकार देगी। वहीं कैबिनेट ने ब्याज सहायता योजना में लाभ को 2 फीसदी से बढ़ाकर 2.5 फीसदी करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। सरकार के इस फैसले से 95 लाख डेयरी किसानों को लाभ होगा।

कैबिनेट की बैठक के बाद फैसले की जानकारी देते हुए केंद्रीय

कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ 5.5 करोड़ किसानों ने उठाया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत कुल 13,000 करोड़ रुपये का प्रीमियम एकत्रित हुआ। मंत्री ने कहा कि 60 हजार करोड़ रुपये के बीमा दावे को स्वीकृति दे दी गई है। किसानों के लिए कई हितैषी कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। मंत्रिमंडल ने फसल बीमा योजना में संशोधन को मंजूरी दी, इसे किसानों के लिए स्वैच्छिक बनाया गया। कृषि मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अभी केंद्र सरकार और राज्य सरकार प्रीमियम का 50-50 फीसदी योगदान देती है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट के किसानों के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है, यहां फसल बीमा प्रीमियम में 90 फीसदी योगदान केंद्र और 10 फीसदी राज्य का रहेगा। इसके अलावा 3 फीसदी योजना की राशि प्रशासनिक व्यवस्था पर रहेगी।

सुरक्षाबलों ने मुठभेड़ में मार गिराए तीन आतंकी

श्रीनगर (आरएनएस)। दक्षिणी कश्मीर के पुलवामा जिले में बुधवार को सुरक्षा बलों ने तलाश एवं घेराबंदी अभियान के दौरान मुठभेड़ में तीन आतंकवादियों को मार गिराया। आधिकारिक सूत्र ने इसकी जानकारी दी। अधिकारियों ने कहा कि उन्हें गुप्त सूचना मिली थी कि आतंकवादी इस इलाके में छिपे हुए हैं। राष्ट्रीय राइफल्स की टुकड़ी, जम्मू-कश्मीर पुलिस की विशेष अभियान समूह और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के जवानों ने आज तड़के पुलवामा के त्राल में संयुक्त रुप से तलाशी अभियान शुरु किया। तलाशी अभियान के दौरान सभी निकासी द्वार सील कर दिए गए थे। उन्होंने कहा कि सुरक्षा बल के जवान जब गांव में घुसे तो आतंकवादियों ने छुप कर गोलीबारी शुरु की और सुरक्षा बलों ने इस गोलीबारी का मुंहतोड़ जवाब दिया। इस दौरान मुठभेड़ में तीन आतंकवादी मारे गए। पुलिस के जवान आसपास के इलाकों में किसी अप्रिय घटना से बचने के लिए एहतियातन तैनात किए गए हैं।

ट्रंप के भारत दौरे से पहले हमले की फिराक में आतंकी संगठन

सुरक्षा एजेंसियां सतर्क

नईदिल्ली (आरएनएस)। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 24-25 फरवरी को भारत आ रहे हैं। इसी के चलते अमेरिकी राष्ट्रपति के दौरे से पहले आतंकवादी किसी बड़े हमले की साजिश रच रहे हैं। खुफिया सूत्रों के मुताबिक आतंकवादी हमले में सॉफ्ट टारगेट को निशाना बना सकते हैं। इसके लिए वह पब्लिक प्लेस पर हमला कर सकते हैं और आम नागरिकों को भी निशाना बनाया जा सकता है। इस खूफिया जानकारी के बाद सुरक्षा एजेंसियां और सतर्क हो गई हैं।

बता दें कि ये खबर ऐसे समय में सामने आई है जब जम्मू-कश्मीर के पुलवामा के त्राल में सुरक्षाबलों को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। मंगलवार देर रात सुरक्षाबलों ने एक ऑपरेशन के दौरान तीन आतंकियों को मार गिराया है। तीनों आतंकवादी आतंकी संगठन अंसार-गजवा-उल- हिंद के सदस्य बताए जा रहे थे। इन तीनों आतंकियों की पहचान जंगीर रफीक वानी, रजा उमर मकबूल भट और उजैर अमिन भट के तौर पर हुई है। बताया जा रहा है कि

इन आतंकियों के पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया है।

बताया जा रहा है कि आतंकवादी संगठन हिजबुल मुजाहिद्दीन किसी बड़े हमले को अंजाम देने की तैयारी में है। इसके अलावा जैश-ए-मोहम्मद भी ट्रम्प दौरे के दौरान आतंकी घटनाओं को अंजाम देने की तैयारी में है। इस बारे में इंटेलिजेंस रिपॉर्ट पहले आ चुकी है।

महत्वपूर्ण एवं खास

शिवाजी की जयंती पर पीएम ने दी श्रद्धांजलि

नईदिल्ली (आरएनएस)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। उन्होंने कहा, 'भारत माता की महान संतानों में एक, साहस, करुणा तथा सुशासन के प्रतिमान असाधारण छत्रपति शिवाजी महाराज को उनकी जयंती पर नमन करता हूं। उनका जीवन लाखों लोगों को प्रेरित करता है।'शिवाजी महाराज ने शौर्यपूर्ण योद्धा और महान प्रशासक के रूप में अपनी छवि बनाई। मजबूत नौसेना बनाने से लेकर अनेक जनमुखी नीतियां लागू करने के साथ वह सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट थे। उन्हें अन्याय और धमकी का प्रतिकार करने के लिए हमेशा जाना जाएगा।

दिल्ली आने वालीं कई ट्रेनें घंटों लेट

नईदिल्ली (आरएनएस)। दिल्ली आ रहीं 9 ट्रेनें 1 घंटे से लेकर 3 घंटे 45 मिनट तक लेट बताई जा रही हैं, जिनमें सबसे ज्यादा लेट भागलपुर आनंद विहार गरीब रथ एक्सप्रेस है जो 3 घंटे 45 मिनट की देरी से दिल्ली आ रही है। जबकि जबलपुर निजामुद्दीन एक्सप्रेस 3 घंटे 15 मिनट, गाजीपुर आनंद विहार टर्मिनल एक्सप्रेस 2 घंटे, पुरी नई दिल्ली पुरुषोत्तम एक्सप्रेस 2 घंटे 45 मिनट, डिब्रूगढ़ दिल्ली ब्रह्मपुत्र मेल 3 घंटे, हावड़ा नई दिल्ली पूर्वा एक्सप्रेस 2 घंटे 15 मिनट, वास्को निजामुद्दीन गोवा एक्सप्रेस 2 घंटे 45 मिनट, जोधपुर दिल्ली सराय रोहिल्ला एक्सप्रेस 2 घंटे और आनंद विहार रीवा एक्सप्रेस 1 घंटे की देरी से आ रही हैं।

दिल्ली में बढ़ा वायु प्रदूषण एनसीआर में गुणवत्ता खराब श्रेणी में

नईदिल्ली (आरएनएस)। दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में बुधवार को वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 273 रिकॉर्ड किया गया। यह जानकारी केंद्र संचालित सिस्टम ऑफ एयर चालिटी एंड वेदर फॉरकास्ट एंड रिसर्च (सफर) ने दी। क्षेत्र में प्रमुख प्रदूषक तत्व पीएम 10 और पीएम 2.5 की संख्यां क्रमशः 228 और 112 मापी गई। वायु प्रदूषण के लिहाज से यह स्थिति खराब श्रेणी में है। हालांकि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) की भविष्यवाणी के अनुसार बुधवार को गरज-चमक के साथ आंधी-तूफान की संभावना है, ऐसे में वायु गुणवत्ता का स्तर गिर सकता है। सफर के अनुसार, पश्चिमी विक्षोभ, उत्तरी-पश्चिमी भारतीय क्षेत्र को प्रभावित कर सकता है, जिससे वायु गति में तेजी आ सकती है। एक्यूआई 20 फरवरी तक खराब श्रेणी के निचले स्तर पर जा सकता है। वहीं 21 फरवरी तक वायु गुणवत्ता में सुधार हो सकता है।

राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की पहली बैठक आज

नईदिल्ली (आरएनएस)। राम जन्म भूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की पहली औपचारिक बैठक बुधवार को शाम 5 बजे दिल्ली में होगी। इसमें शामिल होने के लिए अयोध्या के तीनों ट्रस्टी महंत दिनेद्र दास, विमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र और डॉ. अनिल मिश्र दिल्ली आ गए है। शंकराचार्य बासुदेवानन्द जी सरस्वती मंगलवार को ही दिल्ली पहुंच गए थे। इसके अलावा जानकारी मिली है कि महंत नृत्यगोपाल दास और विहिप नेता चंपत राय को भी ट्रस्ट की बैठक में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। संभावना जताई जा रही है कि बैठक के दौरान नृत्य गोपाल और विहिप नेता चंपत राय को ट्रस्ट में शामिल करने का प्रस्ताव पेश किया जा सकता है।

बजट में किसानों की समस्या का कोई हल नहीं

नईदिल्ली (आरएनएस)। कांग्रेस की उत्तर प्रदेश की प्रभारी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने योगी आदित्यनाथ सरकार के बजट पर तंज कसते हुए कहा है कि बजट तो आ गया लेकिन इसमें लोगों और खास कर किसानों की समस्या का कोई हल नहीं है। गांधी ने बुधवार को तंज कसते हुए कहा, उत्तर प्रदेश सरकार का बजट आया है। उन्होंने कहा कि सरकार सिर्फ बजट लेकर आयी है और इसमें प्रदेश के किसानों से जुड़ी किसी भी समस्या के हल के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया है।

भारतीय नौसेना ने जहाजों, पनडुब्बियों की रीफिट तथा अवसंरचना तैयारियों की समीक्षा की

नईदिल्ली (आरएनएस)। भारतीय नौसेना का वार्षिक रीफिट सम्मेलन (एआरसी) तथा वार्षिक अवसंरचना सम्मेलन (एआईसी) 18 फरवरी को पूर्वी नौसेना कमान विशाखापत्तनम मुख्यालय में प्रारंभ हुआ। दो दिन के सम्मेलन की अध्यक्षता वाइस एडमिरल जी.एस. पब्बी, एवीएसएम, वीएसएम चीफ ऑफ मेटेरियल (सीओएम) एकीकृत मुख्यालय, रक्षा मंत्रालय (नौसेना) ने की। सम्मेलन में नौसेना मुख्यालय, नौसेना के तीनों कमान, तीनों सेनाओं की अंडमान तथा निकोबार कमान, पोर्ट ब्लेयर, डॉकयार्ड, मरम्मत यार्ड तथा नौसेना के मेटेरियल संगठनों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। प्रतिनिधि भारतीय नौसेना के सभी जहाजों और पनडुब्बियों को रीफिट करने (फिर से दुरुस्त करने) की योजनाओं पर चर्चा करेंगे और भारतीय नौसेना की बढ़ती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अवसंरचना को मजबूत बनाने की योजना तैयार करेंगे। अपने उद्घाटन भाषण में वाइस एडमिरल अतुल कुमार जैन, पीवीएसएम, एवीएसएम, वीएसएम, फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ, ईएनसी ने प्रतिनिधियों का स्वागत किया और नौसेना प्लेटफॉर्मो की युद्ध उपलब्धता सुनिश्चित करने में किए जा रहे समर्पित प्रयासों की सराहना की। उन्होंने समुद्र में प्लेटफॉर्मो के सतत संचालन की दिशा में नौसेना रिपेयर यार्ड की भूमिका की सराहना की। चीफ ऑफ मेटेरियल (सीओएम) ने अपने संबोधन में कर्मियों तथा सामग्री की सुरक्षा पर फोकस के साथ जहाजों तथा पनडुब्बियों को रीफिट करने की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए इस आयोजन की सराहना की।

विहिप के मॉडल पर ही बनेगा राम मंदिर

नई दिल्ली (आरएनएस)। अयोध्या में भगवान राम का मंदिर विश्व हिंदू परिषद के मॉडल पर ही बनेगा। मंदिर निर्माण की तारीख 15 दिनों के बाद तय की जाएगी। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की पहली बैठक में इस आशय का फैसला लिया गया। बैठक में राम जन्मभूमि न्यास के मुखिया महंत नृत्य गोपाल दास को नामित करने के बाद उन्हें ट्रस्ट की कमान दे दी गई। जबकि विहिप उपाध्यक्ष चंपत राय को ट्रस्ट का महामंत्री तो गोविंद गिरी को ट्रस्ट का कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी और उनके पूर्व प्रधान सचिव रहे नृपेंद्र मिश्रा को भवन निर्माण समिति का चेयरमैन बनाया गया है।

शीघ्र ही वोटर से लिंक होगा आधार कार्ड

नईदिल्ली (आरएनएस)। अगर आपके पास दो वोटर कार्ड है तो आप भी सतर्क हो जाएं क्योंकि अब चुनाव में किसी तरह की भी हेराफेरी को चुनाव आयोग बर्दाश्त नहीं करेगा। चुनाव ईमानदारी से और नियम के अनुसार हो इसी के चलते चुनाव आयोग ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है।

चुनाव आयोग ने सरकार के साथ चुनाव सुधार प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की एक बार फिर पहल करते हुए प्रत्याशियों द्वारा गलत हलफनामा देने और फर्जी खबरों के प्रसार को निर्वाचन प्रक्रिया दूषित करने वाले अपराध की श्रेणी में रखने का प्रस्ताव दिया है, जिससे निर्वाचित होने के बाद दोषियों की सदस्यता समाप्त की जा सके।

चुनाव सुधार को लेकर मंगलवार को विधि मंत्रालय में सचिव जी नारायण राजू के साथ मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा, चुनाव आयुक्त अशोक लवासा और सुशील चंद्रा की बैठक में इन मुद्दों पर चर्चा की गई। जानकारी के अनुसार चुनाव आयोग ने मांग की थी जनप्रतिनिधि एक्ट में बदलाव कर उसे आधार को वोटर लिस्ट से जोड़ने की इजाजत दी जाए, ताकि गलत तरीके से वोटर आई कार्ड बनवाने वालों पर लगाम लग सके। इस मुद्दे पर चर्चा की

गई और मंत्रालय ने सहमति जता दी है।

आधार को वोटर आई कार्ड से जोड़ने के मुद्दे पर कानून मंत्रालय ने चुनाव आयोग को कहा है कि वह इस बात को सुनिश्चित करे कि लिंक होने का बाद आधार के जरिए सूचना लीक नहीं हो सके। आयोग ने हाल ही में डेटा लीक को रोकने के लिए जरूरी कदमों की सूची बनाई है। अगर चुनाव प्रक्रिया में बदलाव हुआ तो प्रवासी उस क्षेत्र में तब ही वोट कर सकेगा जब वह वहां रहा हो। चुनाव आयोग चाहता है कि वह अधिक से अधिक युवाओं को वोटर लिस्ट में शामिल करे।

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) द्वितीय चरण को मंजूरी

नई दिल्ली (आरएनएस)। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2024-25 तक स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) एसबीएम (जी) के द्वितीय चरण को मंजूरी दे दी है, जो खुले में शौच मुक्त प्लस (ओडीएफ प्लस) पर ध्यान केंद्रित करेगा। जिसमें ओडीएफ स्थिरता और ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन (एसएलडब्ल्यूएम) शामिल हैं। यह कार्यक्रम यह सुनिश्चित करने की दिशा में भी काम करेगा कि कोई भी पीछे न रहे और सभी लोग शौचालय का उपयोग करें। ठड (ळ) चरण-द्वितीय को मिशन मोड में भी लागू किया जाएगा, जिसमें केंद्र और राज्य के शेयरों सहित 2020-21 से 2024-25 की अवधि के लिए कुल अनुमानित बजट अनुमानित वित्तीय लागत रु। 25,497 करोड़ होगी। इसके अतिरिक्त 15 वें वित्त आयोग ने आगामी वित्तीय वर्ष के लिए ग्रामीण स्थानीय निकायों द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली ग्रामीण जलापूर्ति और स्वच्छता के लिए 30,375 करोड़ रुपये का प्रस्ताव रखा है। ओडीएफ प्लस कार्यक्रम विशेष रूप से ग्रे वाटर मैनेजमेंट के लिए मनरेगा के साथ अभिसरण करेगा और नए लॉन्च किए गए जल जीवन मिशन का पूरक भी होगा।

सिविल जज बार कोटे से जिला जजों के पदों के लिए सीधी भर्ती के पात्र नहीं

» सुप्रीम कोर्ट का आदेश

नईदिल्ली (आरएनएस)। उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को एक अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि सिविल जज कोटे के तहत जिला जज के तौर पर सीधी नियुक्ति के पात्र नहीं हैं। इसके लिए वकालत में सात साल की प्रैक्टिस जरूरी है। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा, न्यायमूर्ति विनीत सरन और न्यायमूर्ति एस रवीन्द्र भट की खंडपीठ ने कहा कि सिविल जज बार कोटे से जिला जजों के पद पर सीधी भर्ती के लिए पात्र नहीं हैं। संविधान के अनुच्छेद 233(दो) के तहत जिला जज के पद पर पात्रता के लिए सात साल का प्रैक्टिस आवश्यक है। न्यायालय ने कहा कि मजिस्ट्रेट या मुंसिफ की जिला जज के पद के लिए सीधे तौर पर नियुक्ति नहीं हो सकती।

उन्हें भी बाकी उम्मीदवारों की तरह सात साल की प्रैक्टिस के बाद इम्तिहान पास होने की शर्त पूरी करनी होगी। न्यायालय ने यह भी उच्च न्यायिक सेवाओं में वकीलों की सीधी भर्ती परीक्षा के लिए भी सात साल की वकालत का अनुभव जरूरी है। दिल्ली हाईकोर्ट में पांच अतिरिक्त जिला जज (एडीजे) की भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए थे, इसमें शर्त रखी गई थी। कि इस पद के लिए वकील को सात साल की प्रैक्टिस होना अनिवार्य है।

भारत के 22वें विधि आयोग के संविधान को मिली मंजूरी

नई दिल्ली (आरएनएस)। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आधिकारिक राजपत्र में संविधान के आदेश के प्रकाशन की तारीख से तीन साल की अवधि के लिए भारत के दूसरे कानून आयोग को मंजूरी दी है। भारत का विधि आयोग समय-समय पर भारत सरकार द्वारा गठित एक गैर-वैधानिक निकाय है। आयोग का गठन मूल रूप से 1955 में किया गया था और इसे हर तीन साल में फिर से गठित किया जाता है। भारत के इक्कीसवें विधि आयोग का कार्यकाल 31 अगस्त, 2018 तक था।विभिन्न विधि आयोग देश के कानून के प्रगतिशील विकास और संहिताकरण के लिए महत्वपूर्ण योगदान देने में सक्षम हैं। विधि आयोग ने अब तक 277 रिपोर्ट प्रस्तुत की हैं। आधिकारिक गजट में अपने आदेश के प्रकाशन की तारीख से तीन साल की अवधि के लिए 22 वां विधि आयोग का गठन किया जाएगा। इसलिए केंद्रीय कैबिनेट में यह प्रस्ताव मंजूर किया गया है। केंद्र सरकार को कानून के विभिन्न पहलुओं पर एक विशेष निकाय की सिफारिशों का लाभ होगा जो आयोग को उसके अध्ययन और सिफारिशों के लिए संदर्भ के अनुसार सौंपे जाते हैं। विधि आयोग केंद्र सरकार या सू-मोटू द्वारा किए गए एक संदर्भ पर, कानून में शोध करेगा और उसमें सुधार करने और नए कानून बनाने के लिए भारत में मौजूदा कानूनों की समीक्षा करेगा। यह प्रक्रियाओं में देरी को खत्म करने, मामलों के त्वरित निपटान, मुकदमेबाजी की लागत में कमी आदि के लिए न्याय वितरण प्रणाली में सुधार लाने के लिए अध्ययन और अनुसंधान भी करेगा। ऐसे कानूनों की पहचान करना जिनकी अब आवश्यकता या प्रासंगिक नहीं है और उन्हें तुरंत निरस्त किया जा सकता है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के प्रकाश में मौजूदा कानूनों की जांच करें और सुधार और सुधार के तरीके सुझाएं और ऐसे सिद्धांतों का सुझाव भी दें, जो निर्देश सिद्धांतों को लागू करने और संविधान की प्रस्तावना में निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक हो सकते हैं।

अचानक 'हुनर हाट' पहुंचे पीएम मोदी ने कारीगरों का बढ़ाया उत्साह

नई दिल्ली (आरएनएस)। देश में अल्पसंख्यक समुदाय के कारीगरों व शिल्पकारों के सशक्तिकरण की दिशा में राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली के इंडिया गेट लॉन में चल रहे 'हुनर हॉट' में में बुधवार को अचानक पहुंचे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को देख इस मेले में हिस्सा ले रहे देश के विभिन्न राज्यों के कारीगरों, शिल्पकारों और आम लोगों का चेहरे खिल उठे। पीएम मोदी ने उठा। पीएम मोदी ने 'हुनर हॉट' में लगाए गये कई स्टॉलों पर पहुंचे और कारीगरों के साथ आम लोगों से बातचीत ही नहीं, कि बल्कि उन्होंने कुल्हड़ की चाय पीने के साथ बिहार के स्पेशल लिट्टी-चोखा का भी स्वाद चखा।

यहां इंडिया गेट पर आयोजित हुनर हॉट में बुधवार को अचानक पीएम मोदी पहुंचे तो हर कोई उत्साहित नजर आया। वैसे भी किसी कारीगर की मेहनत देखने अगर खुद पीएम पहुंच जाएं तो किसी कारीगार के लिए इससे अच्छा सरप्राइज और क्या हो सकता है। हुनर हाट में कारीगर अपने बीच पीएम मोदी को देखकर बेहद उत्साहित नजर आए। पीएम मोदी ने ट्विटर पर लिखा कि आज लंच में लिट्टी चोखा और गर्म चाय का आनंद लिया। पीएम मोदी हुनर हाट भ्रमण के दौरान बिहार के मशहूर लिट्टी चोखे का भी आनंद लिए। वहीं उन्होंने खटिया (चारपाई) पर बैठकर कुल्हर वाली चाय का भी लुफ्त उठाया। इस दौरान उन्होंने बिहार के स्वादिष्ट व्यंजन लिट्टी चोखा का भी आनंद उठाया। इसकी तस्वीरें पीएम मोदी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर की हैं।

गृहमंत्री शाह से मिले अरविंद केजरीवाल

» विभिन्न मुद्दो पर हुई चर्चा, केंद्र के साथ मिलकर काम करने की जताई इच्छा

नई दिल्ली (आरएनएस)। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उनके आवास पर मुलाकात की। दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद दोनों नेताओं की यह पहली मुलाकात है, जो करीब 20 मिनट तक चली। इस मुलाकात में दिल्ली के तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई।

अरविंद केजरीवाल ने मुलाकात के बाद कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात बहुत ही फलदायी रही। दिल्ली से जुड़े तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई। हम दोनों सहमत हुए कि दिल्ली के विकास के लिए मिलकर काम करेंगे। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली से जुड़े कई मुद्दों को लेकर हम दोनों इस बात को लेकर सहमत हुए कि दिल्ली के विकास के लिए मिलकर काम करेंगे। बाद में यह पूछे जाने पर कि क्या मुलाकात के दौरान शाहीन बाग के मसले पर भी गृह मंत्री के साथ कोई चर्चा हुई तो केजरीवाल ने साफ कहा कि इस पर कोई चर्चा नहीं हुई। गौरतलब है कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं है और कानून-व्यवस्था सहित कई अहम जिम्मेदारी केंद्र सरकार के अधीन है। केजरीवाल सरकार के पहले

कार्यकाल में केंद्र और राज्य सरकार के बीच लगातार टकराव होता रहा। हालांकि इस बार केजरीवाल ने सहयोग के रास्ते पर चलने की इच्छा जताई है। गौरतलब है कि हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में गृहमंत्री अमित शाह ने बेहद आक्रामक तरीके से प्रचार किया था। उन्होंने शाहीन बाग सहित कई मुद्दों पर केजरीवाल सरकार को घेरने की कोशिश की थी। चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 70 विधानसभा सीटों में से 62 पर जीत हासिल की जबकि बीजेपी को 8 सीटों से संतोष करना पड़ा।